

# 'मिशन एक ट्रिलियन डालर' के लिए हर विभाग में नोडल अफसर

सीएम ने दिया निर्देश, डेलाइट इंडिया संग **समन्वय बनाएंगे** अधिकारी

**राज्य व्यूरो, लखनऊ :** प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डालर बनाने के लिए योगी सरकार ने पूरी रूपरेखा बनाकर काम शुरू कर दिया है। इस लक्ष्य को मिशन का रूप देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर विभाग में नोडल अधिकारी बनाने का निर्देश दिया है। यह अधिकारी हाल ही में चयनित सलाहकार कंपनी डेलाइट इंडिया के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाएगी। कंपनी मुख्यमंत्री के सामने एक जनवरी, 2023 तक अंतिम तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था पांच ट्रिलियन डालर तो सीएम योगी ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डालर बनाने का लक्ष्य तय किया है। प्रदेश में इस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने सलाहकार कंपनी के रूप में निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए डेलाइट इंडिया का चयन किया है। कंपनी को पहली तकनीकी रिपोर्ट अनुबंध हस्ताक्षर होने के बाद 90 दिन में यानी दो नवंबर तक सौंपनी है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों को निर्देशित किया है कि डेलाइट इंडिया के प्रतिनिधियों के संपर्क करने पर उन्हें विभाग के बारे में रणनीति



योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

दो नवंबर तक ड्राफ्ट और एक जनवरी तक कंपनी देगी अंतिम तकनीकी रिपोर्ट

10 सेक्टरों के 50 से अधिक विभागों का होगा परीक्षण

एक ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए 10 सेक्टरों के 50 से अधिक विभागों का परीक्षण किया जाएगा। इन सभी विभागों में चल रही योजनाओं और धरातल पर उसके प्रभाव का परीक्षण किया जाएगा। उसी के आधार पर विभागवार रणनीति तैयार की जाएगी और फिर उसे अमल में लाया जाएगा।

## अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होगी ब्रांड यूपी की चर्चा

सरकार ने जनवरी में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां भी जोरशोर से शुरू कर दी हैं। समिट में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड यूपी की खूबियों और निवेश के फायदों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसमें ईज आफ डूइंग विजनेस के अलावा प्रदेश में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं, संसाधनों की जानकारी निवेशकों को दी जाएगी। इसके अलावा डेलाइट इंडिया के सुझावों और रणनीति को भी शामिल किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित किया जा सके।

और तकनीकी रिपोर्ट तैयार करने में आवश्यक सहयोग दिया जाए। इसके लिए विभागों में एक-एक नोडल अधिकारी की तैनाती कर दी जाए। नियोजन विभाग ने सलाहकार कंपनी को अभिलेख और आंकड़े देने के लिए सभी अपर मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों को पत्र भी लिख दिया है। कंपनी की ओर से तैयार की जा रही पहली ड्राफ्ट तकनीकी रिपोर्ट पर विभागों के मत लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति विचार करेगी। इसके बाद आवश्यक संशोधनों से सलाहकार कंपनी को सूचित किया जाएगा। इन संशोधनों का समावेश करते हुए कंपनी अंतिम तकनीकी रिपोर्ट एक जनवरी, 2023 तक प्रस्तुत करेगी। उसका प्रस्तुतीकरण योगी के समक्ष किया जाएगा, जिस पर वह अंतिम निर्णय लेंगे।